



BACKGROUNDEERS
Press Information Bureau
Government of India

कतार से लेकर क्यूआर कोड तक : भारत की भुगतान क्रांति

प्रत्येक भारतीय के लिए तेज़, सरल और अधिक समावेशी लेन-देन

11 अप्रैल, 2026



कुछ समय पहले तक, एक साधारण वित्तीय लेन-देन के लिए समय, मेहनत और धैर्य जरूरी होता था। बिलों का भुगतान करने के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था। पैसे भेजने के लिए बैंक जाना, फॉर्म भरना और पुष्टि के लिए कई दिनों तक इंतज़ार करना पड़ता था। भारत में उन लाखों लोगों के लिए जिनके पास बैंकिंग सुविधा नहीं थी, इसका मतलब था वित्तीय प्रणाली से बाहर रहना। हालांकि, ऐसा भारत अब अतीत बन चुका है।

भारत की वित्तीय यात्रा सदियों में विकसित हुई है—वस्तु विनिमय प्रणाली और कौड़ी सीप से लेकर सिक्कों, कागज़ी मुद्रा और चेक तक। अपने आधुनिक इतिहास के अधिकांश समय, लेन-देन का प्रमुख माध्यम नकदी बना रहा। हालांकि चेक और डिमांड ड्राफ्ट ने भुगतान को औपचारिक रूप दिया, वे धीमे थे और केवल सीमित वर्ग तक ही सुलभ थे। बैंकिंग ढांचा मुख्यतः शहरी क्षेत्रों तक सीमित थी, जिससे ग्रामीण और दूरदराज़ की आबादी वंचित रह गई।

2000 के शुरुआती दशक ने भुगतान प्रणाली में डिजिटल परिवर्तन की शुरुआत की। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2004 में रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) और 2010 में इमीडिएट पेमेंट सर्विस (आईएमपीएस) जैसी प्रणालियाँ शुरू कीं, जिससे तेज़ और चौबीस घंटे धन का हस्तांतरण संभव हुआ। ये महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ थीं, लेकिन इनकी

पहुँच मुख्यतः उन्हीं लोगों तक सीमित रही जो पहले से ही बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा थे, और अभी भी अनेक लोगों के लिए औपचारिक वित्तीय सेवाओं की पहुँच सीमित रही।

भारत की एक बड़ी आबादी औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर रही—उनकी ऋण, बीमा या सुरक्षित बचत जैसी सुविधाओं तक पहुँच नहीं थी। एक स्केलेबल, समावेशी और रियल-टाइम डिजिटल ढांचे की कमी का मतलब था कि आर्थिक विकास के लाभ सभी तक पूरी तरह नहीं पहुँच पा रहे थे। एक परिवर्तनकारी बदलाव की आवश्यकता स्पष्ट थी, और इसी आवश्यकता ने भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति की नींव रखी।

जेएएम ट्रिनिटी: डिजिटल बैंकिंग के लिए एक संरचनात्मक बदलाव

भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति एक मजबूत आधारभूत संरचना पर टिकी है, जिसमें तीन प्रमुख स्तंभ शामिल हैं—**प्रधान मंत्री जन-धन योजना (जन धन)**, **आधार**, और **मोबाइल कनेक्टिविटी**। इन्हें सामूहिक रूप से **जेएएम ट्रिनिटी** कहा जाता है। प्रत्येक स्तंभ का अपना अलग उद्देश्य है, लेकिन साथ मिलकर इन्होंने लीकेज को कम करके, औपचारिक बैंकिंग में भरोसा बढ़ाकर, और नागरिकों को डिजिटल सेवाओं से जुड़ने के लिए तैयार करके वित्तीय इकोसिस्टम को मजबूत किया है।

“जेएएम ट्रिनिटी ने हमारी बैंकिंग प्रणाली को पूरी तरह एक नए स्तर पर पहुँचा दिया है।”

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

प्रधान मंत्री जन-धन योजना ने बड़े पैमाने पर शून्य-बैलेंस खाते खुलवाने के माध्यम से लाखों लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा है, जिससे सबसे वंचित वर्ग भी वित्तीय रूप से जुड़ सका है। **आधार** ने एक विश्वसनीय डिजिटल पहचान प्रदान करके इस बुनियाद को और मजबूत किया है, जिससे बेरोकटोक सेवाएं प्रदान करने का सटीक लक्ष्य और निर्बाध वितरण संभव हुआ है। इन दोनों के पूरक के रूप में, **मोबाइल कनेक्टिविटी और इंटरनेट पहुँच** के तेज़ी से विस्तार ने नागरिकों को संचार, प्रमाणीकरण और लेन-देन के लिए एक सुविधाजनक और रियल-टाइम माध्यम प्रदान किया है।

इस एकीकृत ढांचे को **प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी)** प्रणाली के माध्यम से पूर्ण रूप मिला, जिसने सरकारी लाभों को सीधे बैंक खातों में पहुँचाने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। बिचौलियों को कम करके और पारदर्शिता बढ़ाकर, डीबीटी ने दक्षता में सुधार किया है और साथ ही डिजिटल प्रणालियों में विश्वास भी मजबूत किया है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि यह परिवर्तन केवल पहुँच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने सहभागिता को भी सक्षम बनाया है। जैसे-जैसे नागरिक डीबीटी से जुड़े, वे डिजिटल वित्तीय लेन-देन के प्रति अधिक परिचित होते गए, जिससे यूनीफाइट पेमेन्ट्स इंटरफेस (यूपीआई) जैसे प्लेटफॉर्म व्यापक रूप से अपनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

यूपीआई : एक क्रांतिकारी नवाचार

2016 में, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने यूपीआई पेमेन्ट्स इंटरफेस (यूपीआई) की शुरुआत की—एक ऐसी प्रणाली जिसने भारत में पैसे के लेन-देन के तरीके को मूल रूप से सरल बना दिया। अपने मूल में, यूपीआई किसी भी बैंक खाते को एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के माध्यम से दूसरे खाते से जोड़ने की सुविधा देता है, जिससे विस्तृत बैंकिंग जानकारी साझा करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।








यूपीआई का विचार अपनी विलक्षण था। अब न तो खाता नंबर याद रखने की जरूरत है और न ही जटिल विवरण भरने की। यह प्रणाली खाता संख्या और आईएफएससी कोड जैसे जटिल इनपुट को एक आसान इंटरफेस से बदल देती है। उपयोगकर्ताओं को केवल एक मोबाइल नंबर, एक यूपीआई आईडी और सुरक्षित प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है, जिससे वे तुरंत धन हस्तांतरण कर सकते हैं। लेन-देन रियल-टाइम में होते हैं, 24x7 उपलब्ध रहते हैं, और विभिन्न बैंकों व ऐप्स के बीच सहज रूप से काम करते हैं।

यह पारस्परिकता ही यूपीआई के तेज़ विस्तार का मुख्य कारण रही है। **2021 में 216 बैंकों से बढ़कर जनवरी 2026 तक 691 बैंकों तक पहुँचते हुए**, यह एक एकीकृत भुगतान संरचना बन गई है, जहाँ उपयोगकर्ता अपने किसी भी बैंक या प्लेटफॉर्म से आसानी से लेन-देन कर सकते हैं। इसके साथ ही, इसकी कम लागत वाली संरचना ने व्यक्तियों और व्यापारियों दोनों के लिए बाधाओं को कम किया है और बैंकों व फिनटेक कंपनियों के बीच नवाचार को बढ़ावा दिया है।

जैसे-जैसे यूपीआई का विस्तार हुआ, इसका प्रभाव केवल भुगतान की सुविधा तक सीमित नहीं रहा। इसने व्यक्तियों, छोटे व्यवसायों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों की वित्तीय प्रणाली में भागीदारी के तरीके को बदलना शुरू कर दिया। डिजिटल लेन-देन अधिक सुलभ, विश्वसनीय और विभिन्न क्षेत्रों व आय वर्गों में व्यापक रूप से अपनाए जाने लगे।

यूपीआई के आँकड़े: पैमाना, गति और वैश्विक नेतृत्व

 21.70 बिलियन जनवरी 2026 में ही किए गए लेन-देन	 28.33 लाख करोड़ रुपये जनवरी 2026 में संसाधित कुल मूल्य	 81 प्रतिशत भारत में सभी खुदरा डिजिटल लेन-देन में हिस्सा
 49 प्रतिशत	 यूपीआई: संख्या के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी रियल-टाइम भुगतान प्रणाली ¹	10 वर्ष से कम समय में

¹ <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2200569®=3&lang=1>

वैश्विक रियल-टाइम भुगतान लेन-देन में भारत की हिस्सेदारी

दुनिया के अग्रणी भुगतान इकोसिस्टम को बनाने में लगा समय

सहूलियत के अलावा: वित्तीय पहुंच का विस्तार

यूपीआई केवल भुगतान को सरल बनाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने वित्तीय प्रणाली में भागीदारी के स्वरूप को भी बदल दिया है। त्वरित और कम लागत वाले लेन-देन को सक्षम बनाकर, इसने नकदी पर निर्भरता को कम किया है, दक्षता बढ़ाई है और लाखों लोगों के लिए औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच खोली है। छोटे व्यापारियों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए यह बदलाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ऋण, बीमा और बचत के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं।

इसकी असली कहानी लेन-देन की संख्या में नहीं, बल्कि यह है कि लेन-देन कौन कर रहा है। **ऑटो-रिक्शा चालक** अब क्यूआर कोड के माध्यम से भुगतान स्वीकार कर रहे हैं। **गांवों की मंडियों** में लेन-देन तुरंत निपटाए जा रहे हैं। सड़क किनारे विक्रेताओं को अब छुट्टे पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ती। एक **घरेलू कामगार** भी एक साधारण स्मार्टफोन की मदद से कुछ ही सेकंड में राज्यों के बीच पैसे भेज सकता है। इस प्रणाली में शहरी और ग्रामीण, औपचारिक और अनौपचारिक के बीच की खाई धीरे-धीरे खत्म हो रही है—जो वित्तीय समावेशन की दिशा में एक निर्णायक बदलाव को दर्शाती है।

साथ ही यूपीआई अब एक व्यापक वित्तीय प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित हो रहा है। **यूपीआई लाइट** तेज़ और छोटे मूल्य के भुगतानों को आसान बनाता है, जबकि **यूपीआई ऑटो पे** उपयोगिता बिलों और सब्सक्रिप्शन जैसे आवर्ती खर्चों को सरल और स्वचालित करता है। **यूपीआई पर क्रेडिट की सुविधा** इसके दायरे को और आगे बढ़ाती है, जिससे पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइनों तक पहुंच संभव होती है। इस मजबूत अवसंरचना के आधार पर, एनबीएफसी और फिनटेक कंपनियाँ ऋण प्रदान कर रही हैं, पुनर्भुगतान को सक्षम बना रही हैं और जरूरतों के अनुरूप वित्तीय उत्पाद पेश कर रही हैं—जिससे पूरे देश में औपचारिक वित्तीय सेवाओं की पहुंच लगातार बढ़ रही है।

डिजिटल भुगतान: पहुंच, दक्षता, सुरक्षा और विश्वास बढ़ाना

इस विस्तारित इकोसिस्टम के आधार पर, यूपीआई अब देश की रोज़मर्रा की आर्थिक संरचना का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। जिसे कभी सिर्फ सहूलियत समझा जाता था, वह अब एक विश्वसनीय प्रणाली बन गया है, जो व्यक्तियों, व्यवसायों और वित्तीय संस्थानों—सभी की मदद करता है।

उपयोगकर्ताओं के लिए, इसका अनुभव **सरलता और विश्वास** से परिभाषित होता है। लेन-देन कभी भी, कहीं से भी, एक ही एप्लिकेशन के माध्यम से किए जा सकते हैं, जो कई बैंक खातों से जुड़ा होता है। संवेदनशील बैंकिंग जानकारी साझा करने की आवश्यकता नहीं होती, और अंतर्निहित सुरक्षा उपाय यह सुनिश्चित करते हैं कि भुगतान

सुरक्षित रहें। ऐप्स के भीतर उपलब्ध सहायता सुविधाएँ शिकायत निवारण को भी आसान बनाती हैं, जिससे यह प्रणाली पहली बार उपयोग करने वालों के लिए भी सुलभ हो जाती है।

डिजिटल भुगतान में विश्वास को और मजबूत करते हुए, **भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)** ने 1 अप्रैल 2026 से **डिजिटल भुगतान लेन-देन के लिए उन्नत प्रमाणीकरण तंत्र लागू किए हैं।** दो-स्तरीय प्रमाणीकरण का यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि हर लेन-देन कई स्तरों पर सत्यापित हो—जैसे पिन, बायोमेट्रिक्स या सुरक्षित टोकन के साथ ओटीपी। इससे धोखाधड़ी के जोखिम में उल्लेखनीय कमी आई है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भरोसा और मजबूत हुआ है।

व्यापारियों के लिए, यह नकदी संभालने की आवश्यकता के बिना तेज़ और कुशल तरीके से भुगतान प्राप्त करने का माध्यम प्रदान करता है। इससे व्यवसायों को व्यापक ग्राहक आधार तक पहुंचने में मदद मिलती है, खासकर उन ग्राहकों तक जो कार्ड या नकद के बजाय मोबाइल-आधारित भुगतान को प्राथमिकता देते हैं। चाहे छोटे दुकानों में हो, सड़क बाज़ारों में या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर—लेन-देन तुरंत पूरे होते हैं, जिससे देरी और नकदी प्रबंधन या रिटर्न जैसी परिचालन चुनौतियाँ कम होती हैं।

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए, यह मौजूदा प्रणालियों का उपयोग करते हुए सुरक्षित और रियल-टाइम लेन-देन को सक्षम बनाकर **सेवा वितरण को बेहतर** बनाता है। यह बड़े पैमाने पर व्यक्ति-से-व्यक्ति और व्यापारी भुगतानों का समर्थन करता है, साथ ही मजबूत सुरक्षा उपायों को बनाए रखते हुए दक्षता में सुधार करता है और औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करता है।

भारत का नवाचार: विश्व पर प्रभाव बनाता हुआ

भारत का डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम न केवल घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने में सफल रहा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर एक आदर्श मॉडल के रूप में भी उभरा है। *अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)* और *विश्व बैंक* जैसे संस्थानों ने इसकी व्यापकता, दक्षता और समावेशिता को सराहा है।

वैश्विक नेताओं, जैसे *फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुएल मैक्रों* ने भी भारत की इस उपलब्धि पर गौर किया है कि यूपीआई के माध्यम से हर महीने 20 अरब से अधिक लेन-देन किए जाते हैं—जो किसी भी अन्य रियल-टाइम भुगतान प्रणाली के मुकाबले बेजोड़ है।

यूपीआई अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे बढ़ चुका है और संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, भुटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरीशस और कतर सहित कई देशों में चल रहा है या उनकी भुगतान प्रणालियों से जुड़ा हुआ है। यह बढ़ता हुआ अंतर्राष्ट्रीय विस्तार सीमा-पार लेन-देन को आसान बना रहा है, रकम भेजने में मदद कर रहा है और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हुए वैश्विक फिनटेक परिदृश्य में भारत की भूमिका को और मजबूत कर रहा है।

यूपीआई : भारत में वित्तीय लेन-देन के लिए एक वरदान

यूपीआई ने वित्तीय रूप से जुड़े और वंचित वर्गों के बीच की खाई को समाप्त कर दिया है। आज ग्रामीण और अर्ध-शहरी भारत भी महानगरों की तरह ही तेज़ी और सहजता से लेन-देन कर रहा है।

एक स्वदेशी प्रणाली, जिसे एक दशक से भी कम समय में विकसित किया गया, आज विश्व में अग्रणी बन चुकी है। जो पहल कभी बैंकिंग से वंचित लोगों को जोड़ने के लिए शुरू हुई थी, वह अब रियल-टाइम भुगतान के लिए वैश्विक मानक बन गई है। कतारों से क्यूआर कोड तक की यह यात्रा समावेशी नवाचार की शक्ति को दर्शाती है।

यूपीआई केवल एक भुगतान प्रणाली नहीं है; यह लोगों का मंच है। इसने वित्तीय लेन-देन को तेज़, सरल, पारदर्शी और वास्तव में समावेशी बना दिया है। ऐसा करते हुए, इसने न केवल यह बदला है कि भारत कैसे भुगतान कर रहा है, बल्कि यह भी कि भारत कैसे आगे बढ़ रहा है।

संदर्भ :

वित्त मंत्रालय :

- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2161401®=3&lang=2>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetailm.aspx?PRID=2079544®=3&lang=1>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2240723®=3&lang=2>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2200569®=3&lang=1>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1755394®=3&lang=2>

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय :

- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2224505®=3&lang=2>

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (यूपीआई):

- <https://www.npci.org.in/product/upi/product-statistics>

भारतीय रिजर्व बैंक :

- <https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/NT79258FF36ECA8F4886B3B01F55D166C2B2.PDF>

पीआईबी बैकग्राउंडर्स:

- <https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=149258®=3&lang=1>

पीआईबी रिसर्च

पीके/केसी/केपी